भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2131
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भू-राजनीतिक तनाव पर कूटनीतिक प्रतिक्रिया

2131. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी क्षेत्रों में हाल के भू-राजनीतिक तनावों, जिनमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती स्थिति भी शामिल है, पर भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के सामरिक हितों की रक्षा और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ हाल ही में कोई उच्च-स्तरीय वार्ता या द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) संघर्ष-प्रभावित या राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों में भारतीय छात्रों और प्रवासी भारतीयों का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का आगामी वर्षों में भारत की वैश्विक छवि को बढ़ावा देने और उसकी कूटनीतिक पहुँच का विस्तार करने के लिए किसी नई पहल का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क) सरकार रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को घनिष्ठ बनाकर, आर्थिक एवं वाणिज्य संबंधों को आगे बढ़ाकर, विकासात्मक सहायता और विभिन्न देशों के साथ उत्पादक सहयोग द्वारा भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए, उभरते क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण को संतुलित करती है। भारत की "पड़ोस प्रथम नीति" और व्यापक महासागर दृष्टिकोण पड़ोसी देशों में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना करता है जो नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता हेतु सम्मान, नौका परिवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, बाधा रहित कानून सम्मत वाणिज्य, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सभी देशों की समानता पर आधारित हो।

(ख) और (ङ) भारत ने अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए अनेक देशों के साथ बहुआयामी साझेदारियां की हैं, जिनका व्यापक उद्देश्य राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाना, राजनयिक हितों को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, व्यापक आर्थिक और निवेश वृद्धि, ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना, सतत विकास लक्ष्य, लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाना, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग का विस्तार करना, अवसंरचना का विकास और वैश्विक प्रभाव में वृद्धि करना है।

सरकार विशेष रूप से संघर्ष प्रभावित या राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों में भारतीय छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अतः हमने इन चिंताओं को दूर करने के लिए वॉक-इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद, सीपीग्राम, ई माइग्रेट और सोशल मीडिया जैसे तंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, श्रम और जनशक्ति से संबंधित कुछ विशिष्ट मुद्दों का निपटान करने और भारतीय कामगारों के कल्याण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय करार संपन्न किए गए हैं। सरकार सक्रिय रूप से घटनाक्रम की निगरानी करती है और परामर्शी जारी करती है। आपातकालीन या संकट की स्थिति के दौरान, विदेशों में स्थित हमारे मिशन/केन्द्र संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय नागरिकों को कोंसली सहायता, भोजन, आश्रय, दवा उपलब्ध करवाकर और उनकी भारत वापसी सुकर बनाकर सक्रिय रूप से मदद करते हैं। सरकार बचाव कार्यों के लिए उड़ानों की व्यवस्था सहित अतिरिक्त कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हाल के कुछ निकासी मिशनों में वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन इंद्रावती आदि शामिल हैं।

(ग) पिछले चार महीनों में उच्च-स्तरीय यात्राओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है। उच्च-स्तरीय यात्राएँ विदेशों के साथ संपन्न संबंधों को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भारत के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के स्थापित साधन हैं। इन यात्राओं के माध्यम से, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, अपने सामरिक हितों की रक्षा करता है, विदेश नीति के उद्देश्यों को क्रियान्वित करता है और साथ ही विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

(घ) भारत बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध है और अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय मंचों का रणनीतिक उपयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत अनेक महत्वपूर्ण पहलों को साकार करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के साथ-साथ सक्रियता से अपने हित के क्षेत्रों को आगे बढ़ाता है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप साझेदार देशों के साथ सहयोग बढ़ा है और संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान भारत की विकास पहलों को प्रदर्शित करने और जी20 में वैश्विक दक्षिण की विकासात्मक प्राथमिकताओं और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जी20 नई दिल्ली राजनेताओं के घोषणापत्र में महत्वाकांक्षी और कार्योन्मुखी परिणामों को प्रतिबिंबित किया गया, जिसमें एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना, हरित विकास और पर्यावरण अनुकूलन जीवनशैली (लाईफ) संबंधी पहल, त्वरित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से तकनीकी परिवर्तन और महिलाओं के नेतृत्व में विकास शामिल हैं। ब्रिक्स में भारत की भागीदारी, वैश्विक शासन में सुधार और बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने सहित भारत के रणनीतिक लक्ष्यों और पहलों को आगे बढ़ाने का लाभ प्रदान करती है। हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ सहित ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सुधार और सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार का आह्वान किया है ताकि इसे अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और कुशल बनाया जा सके।

(च) भारत अपने "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" संबंधी दृष्टिकोण के अनुरूप, विकास के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण, वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार, जलवायु और पर्यावरणीय कार्रवाई आदि सहित प्रमुख क्षेत्रों में राजनयिक पहुंच के माध्यम से अपनी वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाता रहेगा।

अनुबंध

पिछले चार महीनों के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की भारत यात्राएँ

क्रम सं.	देश	यात्रा की अवधि
1	महामहिम ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मार्क फिलिप्स, सहकारी गणराज्य गुयाना के प्रधानमंत्री	04 से 07 मार्च 2025
2	महामहिम क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री	16 से 20 मार्च 2025
3	महामहिम ज़ेवियर बेटेल, लक्ज़मबर्ग के उप प्रधान मंत्री, विदेश मामले और विदेश व्यापार मंत्री	17 से 19 मार्च 2025
4	महामहिम मिहाई पोपसोई, मोल्दोवा गणराज्य के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री	17 से 19 मार्च 2025
5	महामहिम डॉ. एडुआर्डो मार्टिनेज डियाज़, क्यूबा के उप प्रधान मंत्री	17 से 19 मार्च 2025
6	महामहिम गेब्रियल बोरिक फ़ॉन्ट चिली गणराज्य के राष्ट्रपति	01 से 05 अप्रैल 2025
7	महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, दुबई के क्राउन प्रिंस, संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री	08 से 09 अप्रैल 2025
8	महामहिम एंटोनियो तजानी, इटली के उप प्रधान मंत्री एवं विदेश मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री	11 से 12 अप्रैल 2025
9	महामहिम जेम्स डेविड वेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति	21 से 24 अप्रैल 2025
10	महामहिम जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको अंगोला गणराज्य के राष्ट्रपति	02 से 04 मई 2025
11	माननीय विंस्टन पीटर्स, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री	29 से 30 मई 2025
12	महामहिम सैंटियागो पेना पैराग्वे गणराज्य के राष्ट्रपति	02 से 04 जून 2025
13	महामहिम मूरत नूर्टलेउ, कजाखस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री	05 से 06 जून 2025

पिछले 4 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्राओं का विवरण

क्रम सं.	देश	यात्रा की अवधि
1	मॉरीशस	11 से 12 मार्च 2025
2	थाईलैंड और श्रीलंका	03 से 06 अप्रैल 2025
3	सऊदी अरब	22 अप्रैल 2025
4	साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया	15 से 18 जून 2025
5	घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया	02 से 09 जुलाई 2025
6	यूनाइटेड किंगडम और मालदीव	23 से 26 जुलाई 2025

पिछले 4 महीनों के दौरान विदेश मंत्री द्वारा की गई यात्राओं का विवरण

क्रम सं.	देश	यात्रा की अवधि
1	यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड	04 से 09 मार्च 2025
2	नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी	19 से 24 मई 2025
3	फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम	08 से 14 जून 2025
4	यूएसए	30 जून से 2 जुलाई 2025
5	सिंगापुर और चीन	13 से 15 जुलाई 2025

*****